(e) Indigenisation is encouraged whereever possible by providing technical assistance to indigenous manufacturers.

**Discount/commission on room rent in I.T.D.C. hotels**

3260. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) what are the details of the decision, if any, taken by the Board of Directors of I.T.D.C. to allow discount/commission on room rent in I.T.D.C. hotels; and

(b) what is the amount of discount/commission allowed on room rent in Ashoka Hotel, New Delhi during 1984-85 to 1987-88?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) ITDC Board of Directors have delegated to Chairman and Managing Director, ITDC full powers to grant concession to clients/customers/employees.

(b) No separate account in respect of the discount allowed on room rent in Ashok Hotel New Delhi is kept. However, as regards commission Paid by the hotel to various agencies during the period in question, the *same)* is given below.

| Year | (Rupees in lakhs) |
|---|---|
| 1984-85 | 7.63 |
| 1985-86 | 12.79 |
| 1986-87 | 18.01 |
| 1987-88 | 20.40 |

**गण्डक नदी पर रेल-सड़क पुल का निर्माण**

3261. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमाओं के साथ लगी गण्डक नदी के ऊपर रेल सड़क पुल के निर्माण के लिये अपना-अपना अंशदान देने पर सहमति व्यक्त की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि छितौनी बगहा रेल सड़क पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया था और उस पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च जा किये चुके हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण कार्य को बन्द किये जाने के क्या कारण हैं और सरकार इस निर्माण कार्य को कब तक पुन: शुरू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर "ना" हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) :** (क) से (घ) सिंचाई मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि गण्डक नदी पर पुल के निर्माण के लिये रेलें छितौनी में स्थापित किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण स्थल का लाभ उठा सकती हैं। पुल की लागत की भागीदारी सिंचाई मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकार तथा रेलों द्वारा की जानी थी। तदनुसार, छितौनी बगहा के बीच, गण्डक नदी पर पुल सहित, रेल सम्पर्क का निर्माण अनुमोदित किया गया और प्रारम्भ किया गया। अब तक 2.48 करोड़ रुपये खर्च किया गया है।

बाद में सिंचाई मंत्रालय बढ़ी हुई लागत का हिस्सा वहन करने के लिए सहमत नहीं हुआ। बिहार सरकार ने भी भागीदारी से इन्कार कर दिया। योजना आयोग ने सिंचाई मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा अपनाए गये रूख को देखते हुए परियोजना को बंद करने की सिफारिश की थी। इस मामले पर योजना आयोग पुन: विचार कर रहा है।